पुषालाल मानसिंहका (पी) लिमिटेड.

बनाम

आयकर आयुक्त, दिल्ली, राजस्थान एवं म.प्र.

5 मई, 1967

[जे.सी. शाह, एस.एम. सीकरी और वी. रामास्वामी,जे.जे]

आयकर अधिनियम 1922 धारा 4(1) (ए) - भाग 'बी' राज्य में निर्यातक भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में खरीददारों को माल बेच रहा है-स्थानीय बैंक के माध्यम से 'सेल्व्स' रेलवे रसीदें भेज रहा है जो क्रेता को भुगतान पर दिया जाएगा- बैंक स्थानीय स्तर पर कुछ बिलों में छूट दे रहा है - चाहे संपत्ति माल पारगमन में हो और आय अर्जित हो रही हो, भाग 'बी' राज्य के बाहर- क्या भाग 'बी' राज्य पर (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 के तहत कर छूट उपलब्ध है।

अपीलकर्ता ने प्रासंगिक अवधि के दौरान भीलवाड़ा में खनन व्यवसाय किया। भाग 'बी' राज्य में और अभ्रक को कोडरमा तक निर्यात किया गया और गिरिडीह क्रमशः भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में स्थित हैं। अपीलकर्ता ने खरीददारों के साथ अनुबंध किया जिसके तहत रेलवे द्वारा कोडरमा और गिरिडीह भेजी जाएगी और रेलवे रसीदें बैंक के माध्यम से भेजी जाएंगी। माल को "सेल्फ" को सौंप दिया गया था और बैंक के पक्ष में रेलवे रसीदों का समर्थन करने के बाद अपीलकर्ता द्वारा विनिमय के बिलों के साथ रेलवे रसीदों को भीलवाड़ा में अपने बैंक में प्रस्तुत किया गया था। बैंक ने, अपनी बारी में, भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में अपनी शाखाओं के पक्ष में रेलवे रसीदों का समर्थन किया और सामान खरीदारों को सौंप दिया गया

केवल तभी जब उन्होंने बैंक की शाखाओं को कीमत का भुगतान किया हो और रेलवे रसीदें प्राप्त कीं हो।

वर्ष 1950-1951 और 1951-1952 के लिए अपीलकर्ता के आयकर मूल्यांकन के दौरान, अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह लाभ के संबंध में भाग 'बी' राज्य (कराधान रियायतें) आदेश 1950 के तहत छूट के लाभ का हकदार था उसके द्वारा की गई बिक्री के लाभ से और आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4(1) (ए) इस लेनदेन

पर लागू नहीं था। आयकर अधिकारी ने माना कि बिक्री भाग 'ए' और भाग 'सी' में हुई थी । इन राज्यों में उन बिक्री से पूरा मुनाफा उन राज्यों में अपीलकर्ता द्वारा अर्जित और प्राप्त किया गया था और इसलिए आदेश के तहत कोई छूट स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने अपीलकर्ता के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि कुछ बिक्री के संबंध में, बिलों में छूट दी गई थी स्थानीय बैंक द्वारा और इसलिए उस सीमा तक भुगतान को भाग 'बी' राज्य में भीलवाड़ा में प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए। अपीलीय सहायक आयुक्त और ट्रिब्यूनल में की गई अपील खारिज कर दी गई और, उच्च न्यायालय ने, एक संदर्भ पर, अपीलकर्ता के खिलाफ भी फैसला सुनाया।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि चूंकि अभ्रक को भाग 'बी' राज्य के भीलवाड़ा में निकाला, संसाधित, छांटा और पैक किया गया था, इसलिए भीलवाड़ा में आय का एक हिस्सा जमा हुआ था और अपलेलेंट किसी भी मामले में, अर्जित लाभ के बंटवारे का दावा करने का हकदार था।

हेल्ड: (i) अपीलकर्ता केवल भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में कोडरमा और गिरिडीह में खरीदारों को स्वामित्व के भुगतान पर खरीद धन का हकदार बन गया और इसलिए अर्जित आय अपीलकर्ता को मिली उन राज्यो में। इसलिए अपीलकर्ता भाग 'बी' राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 के तहत छूट का हकदार नहीं था। [970बी]

जब विक्रेता क्रेता पर एक हुंडी या विनिमय का बिल निकालता है और हुंडी या विनिमय के बिल को संबंधित रेलवे रसीद के साथ अपने बैंकर को सौंपता है ताकि रेलवे रसीद की डिलीवरी क्रेता को हो सके, माल में संपत्ति को क्रेता को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कीमत का भुगतान नहीं कर देता और बैंकर से रेलवे रसीद की डिलीवरी नहीं ले लेता। [968 डी]

किसी निर्धारिती को उसकी वास्तविक प्राप्ति के बिना आय अर्जित हो सकती है। यदि निर्धारिती को आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि आय, उसे प्राप्त हुई है, हालांकि बाद में इसका पता चलने पर इसे

प्राप्त किया जा सकता है। मूल धारणा यह है कि उसे इसका अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिससे वह आय प्राप्त कर सके। [966 बी]

(ii) जब स्थानीय बैंक बिलों में छूट देता है, तो भुगतान हो सकता है भाग 'बी' राज्य में अर्जित आय के रूप में यह नहीं गिना जाएगा। जब बैंक ने कुछ बिलों की राशि का कुछ हिस्सा अपीलकर्ता को जमा कर दिया, यह छूट फॉर्म में निर्दिष्ट शर्तों से स्पष्ट था -बैंक ने कहा कि अपीलकर्ता की जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक बैंक को खरीददारों से भुगतान नहीं मिल जाता। जब अपीलकर्ता ने बैंक के साथ दस्तावेजों पर बातचीत की, तो उसने ऐसा केवल एक भाग के रूप में किया कि यह बैंकिंग व्यवसाय है। बैंक द्वारा बिलों की छूट का मतलब यह नहीं हो सकता कि बैंकरों को माल की बिक्री हुई। इसलिए यदि हुंडी की कीमत के रूप में बैंक द्वारा अपीलकर्ता को कोई धनराशि का भुगतान किया गया था, किसी भी मायने में माल का बिक्री मूल्य नहीं था और बैंक भी ख़रीदार का प्रतिनिधि नहीं था । [969 सी एच]

क्वहुन बनाम ब्रूक्स, [1888] 21 क्यू.बी.डी. 52 पर 59; ई. डी. सैसून एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सी.आई.टी. बॉम्बे सिटी, 26 आई.टी.आर. 27,51; सी.आई.टी. बॉम्बे प्रेसीडेंसी और अदन बनाम चुन्नीलाल बी. मेहता 6 एल.टी.आर. 521; मिराबिता बनाम इंपीरियल ओटोमन बैंक, [1878] 3 एक्स.डी.164, 172 और प्रिंज़ एडालबर्ट, [1917] ए.सी. 586, 589; संदर्भित।

यह तर्क कि अर्जित लाभ को विभाजित किया जाना चाहिए क्योंकि भाग 'बी' राज्य में आय का एक हिस्सा अर्जित किया गया था, उस पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे ट्रिब्यूनल के समक्ष नहीं उठाया गया था। [970ई-एफ]

सी.आई.टी. बॉम्बे बनाम, अहमदभाई उमरभाई एंड कंपनी, 18 आई.टी.आर. 472; एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, बनाम सी.आई.टी. मद्रास, 25 आई.टी.आर. 27 एवं सी.आई.टी. बॉम्बे बनाम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, 42 आई.टी.आर. 589, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 557 और 558 ऑफ़ 1966.

आयकर संदर्भ संख्या 2 ऑफ़ 1963 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल, 1964 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

के. डी. कारखानिस, गणपत राय, ई. सी. अग्रवाल,पी. सी. आगरवाल अपीलकर्ता के लिए (दोनों अपीलों में)।

प्रतिवादी की ओर से एस. टी. देसाई, एस. के. अय्यर और आर. एन. सच्ते (दोनों अपीलों में)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया -

रामास्वामी, जे. ये अपीलें विशेष अनुमति द्वारा लायी गयी हैं। 1963 के आयकर संदर्भ संख्या 2 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल, 1964 के फैसले से। अपीलकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी खदानें, फैक्ट्री और प्रधान कार्यालय राजस्थान के भीलवाड़ा में है, जो प्रासंगिक अवधि में भाग 'बी' राज्य में था। अपीलकर्ता भीलवाड़ा में खनन व्यवसाय करता था और अभ्रक की कटाई, प्रसंस्करण, छंटाई और पैकिंग में लगा हुआ था, जिसे इसके द्वारा कोडमिया और गिरिडीह में निर्यात किया जाता था, जो भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में स्थित थे और वहां खरीदारों को बेचा जाता था। अभ्रक लगभग पूरी तरह से भीलवाड़ा से कोडरमा और गिरिडीह तक रेलवे द्वारा भेजा जाता था। अपीलकर्ता ने लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का पालन किया और विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष 1950-51 और 1951-52 हैं, पिछले वर्ष 2 नवंबर, 1948 से 21 अक्टूबर, 1949 और 22 अक्टूबर, 1949 से नवंबर 9, 1950 तक के वर्ष है, क्रमशः। दो मूल्यांकन वर्षों के दौरान अपीलकर्ता की कुल बिक्री आय मूल्य 19,77,544/- रू थी। अपीलकर्ता ने बैंक की स्थानीय शाखा को बिल प्रस्तुत किये राजस्थान के 15,64,475/- रुपये की सीमा तक और भीलवाड़ा में उस राशि का भुगतान प्राप्त किया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह भाग 'बी' राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 और उसके तहत इन बिक्री से मुनाफे के संबंध में छूट का लाभ पाने का हकदार था। आयकर अधिनियम, 1922 का 4(1)(ए) (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) इसके लेनदेन पर लागू नहीं था। 24 मार्च, 1955 और 31 मई, 1954 के अपने आदेश से आयकर अधिकारी ने

माना कि बिक्री भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में हुई और उन बिक्री से पूरा लाभ अर्जित हुआ और अपीलकर्ता को प्राप्त हुआ। भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में इसलिए भाग 'बी' राज्य (कर रियायतें) आदेश, 1950 के तहत कोई छूट स्वीकार्य नहीं थी।आयकर अधिकारी ने अपीलकर्ता के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि कुछ बिक्री बिलों के संबंध में राजस्थान बैंक द्वारा छूट दी गई थी और उस सीमा तक भुगतान को भाग 'बी' राज्य में भीलवाड़ा में प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए। यह आयकर अधिकारी के पास था: (1) कि छूट के लिए पत्र जाली था, (2) यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता ने अपने कुछ बिलों को छूट के लिए प्रस्तुत किया था, बैंक द्वारा अपने फॉर्म में निर्धारित शर्तों के तहत अपीलकर्ता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई जब तक बैंक को खरीदार से भुगतान प्राप्त नहीं हो गया और इसलिए उन बिलों में कोई छूट नहीं थी जो केवल वसूली के लिए बैंक को सौंपे गए थे। अपील पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20 सितंबर, 1957 द्वारा माना कि आयकर अधिकारी का यह मानना उचित था कि अपीलकर्ता भाग 'बी' राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 के तहत किसी भी छूट का हकदार नहीं था। आगे की अपील पर, अपीलीय न्यायाधिकरण ने 18 अगस्त, 1958 के अपने आदेश द्वारा माना कि अपीलकर्ता को भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में खरीदारों को भेजे गए माल के संबंध में बिक्री आय प्राप्त हुई, न कि भाग 'बी' राज्यों में और इसलिए अपीलकर्ता इसके लिए दावा की गई छूट का हकदार नहीं था। इसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 66(1) के तहत मामला दर्ज किया और उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया गया:

“क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, निर्धारिती मूल्यांकन वर्ष 1950 के लिए खनन व्यवसाय से आय के संबंध में भाग 'बी' राज्य (कराधान रियायतें) आदेश के तहत किसी छूट का हकदार था, आकलन वर्ष 1950-51 और 1951-52 के लिए खनन व्यवसाय से आय के संबंध में ?"

दिनांक 29 अप्रैल, 1964 के अपने निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रश्न का नकारात्मक और अपीलकर्ता के विरुद्ध उत्तर दिया।

बिक्री करने में अपीलकर्ता की विधि इस प्रकार थी: कोडन्ना और गिरिडीह के खरीदारों के प्रतिनिधि भीलवाड़ा आते थे, अभ्रक के विभिन्न गुणों का निरीक्षण करते थे जो

कि अपीलार्थी ने बिक्री के लिए किया था और खरीद के लिए लिखित अनुबंध में प्रवेश किया था। उपरोक्त अनुबंधों को मामले के बयान में अनुबंध 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है और पार्टियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वे उन सभी अनुबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे हम इन अपीलों में संबंधित हैं। इन अनुबंधों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खरीदारों ने अभ्रक की निर्दिष्ट गुणवत्ता, "भीलवाड़ा गोदाम डिलीवरी" इस शर्त पर खरीदी कि खेप कोडरमा या गिरिडीह, जैसा भी मामला हो, भेजा जाएगा और रेलवे रसीदें "बैंक के माध्यम से" भेजी जाएंगी। आगे शर्त यह है कि कीमत का 25 प्रतिशत अग्रिम के रूप में, एक सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा, पैकिंग खर्च खरीदारों द्वारा भुगतान किया जाएगा और खेप भीलवाड़ा में गोदाम से निकलने के बाद, पूरी तरह से खरीदार के जोखिम पर होगा।अनुबंध के इन लिखित नियमों और शर्तों के अलावा, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तथ्य का और निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलकर्ता ने माल को "सेल्फ”को सौंप दिया था और रेलवे रसीदों का समर्थन करने के बाद अपीलकर्ता द्वारा विनिमय के बिलों के साथ रेलवे रसीदें राजस्थान बैंक, भीलवाड़ा को संग्रह के लिए प्रस्तुत की गई थीं। बैंक का पक्ष यह भी पाया गया है कि राजस्थान बैंक ने भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में अपनी शाखाओं के पक्ष में रेलवे रसीदों का समर्थन किया और सामान खरीदारों को तभी वितरित किया गया जब उन्होंने भुगतान किया। बैंक को कीमत दी और रेलवे रसीद प्राप्त की।

भाग 'बी' राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 का पैराग्राफ 4(1)(iii) निम्नलिखित प्रभाव वाला है:

“4. मुख्य रियायतों का दायरा-(1) प्रावधान- इस आदेश के पैराग्राफ 5, 6, उप पैराग्राफ (1) के पैराग्राफ एच ग्राफ 11, 12 और 13 लागू होंगे-

(iii) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में, जो पिछले वर्ष में कर योग्य क्षेत्रों में या भाग ‘बी’ राज्यों के अलावा अन्य कर योग्य क्षेत्रों में निवासी नहीं है, उसकी कुल आय में शामिल आय, लाभ और लाभ का इतना हिस्सा अर्जित होगा या किसी भाग ‘बी’ राज्य में उत्पन्न होते हैं और अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (आई) के खंड (ए) के अर्थ के भीतर अर्जित या उत्पन्न नहीं माने जाते हैं, या प्राप्त नहीं किए जाते हैं या प्राप्त किए गए नहीं माने जाते हैं, भाग ‘बी’ राज्यों के अलावा अन्य कर योग्य क्षेत्र में।"

अधिनियम की धारा 4(1)(ए)में लिखा है:

“4. अधिनियम का अनुप्रयोग.-(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय में सभी आय और लाभ शामिल हैं जो भी स्रोत प्राप्त हो उससे लाभ-

(ए) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में कर योग्य क्षेत्रों में प्राप्त किए गए हैं या प्राप्त किए गए माने जाते हैं, या"

इस मामले में विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है:

बिक्री के अनुबंधों के तहत आय या भुगतान प्राप्त करने का अधिकार कहां से अर्जित या उत्पन्न हुआ? ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार "एक्यू" शब्द का अर्थ "प्राकृतिक वृद्धि या वृद्धि के रूप में गिरना; परिग्रहण या लाभ के रूप में आना" है। "उत्पन्न" शब्द की परिभाषा "उठना, अस्तित्व में आना" के रूप में की जाती है। भाग ‘बी’ राज्य (कराधान रियायत) आदेश के पैरा 4(1)(iii) में "प्राप्त करें" शब्द का उपयोग "उपार्जित" और "उत्पन्न" के समान अर्थ में नहीं किया गया है। शब्द "उपार्जित" और "उत्पन्न" का अर्थ लाभ या लाभ की वास्तविक प्राप्ति नहीं है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग "प्राप्त करें" शब्द के विपरीत किया जाता है और प्राप्त करने के अधिकार का संकेत मिलता है। कोलक्हौं बनाम ब्रूक्स में लॉर्ड जस्टिस फ्राई को "लाभ या लाभ, उत्पन्न होने या अर्जित होने" की अभिव्यक्ति का अर्थ लगाना पड़ा 16 और 17 विक्टोरिया अध्याय 34, धारा 2, अनुसूची 'डी' में और उस संबंध में निम्नानुसार अवलोकन किया गया:

"सबसे पहले, मैं देखूंगा कि कर 'प्राप्त होने वाले या अर्जित होने वाले लाभ' के संबंध में है। मैं उन शब्दों को 'प्राप्त' के अर्थ के रूप में नहीं पढ़ सकता यदि अधिनियम 'प्राप्त किए गए' लाभ और लाभ तक सीमित होता जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाएगा, वह सीमा महामहिम की सभी प्रजा पर उतनी ही लागू होगी जितनी इस देश में रहने वाले विदेशियों पर। इसका परिणाम यह होगा कि उन लाभों पर कोई आयकर देय नहीं होगा जो अर्जित हुए थे लेकिन जो वास्तव में प्राप्त नहीं हुए थे,

हालांकि लाभ राज्य में अर्जित किया गया होगा। इसलिए, मुझे लगता है कि 'उत्पन्न होना या अर्जित होना' शब्द लाभ प्राप्त करने के अधिकार का वर्णन करने वाले सामान्य शब्द हैं।इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी निर्धारिती को उसकी वास्तविक प्राप्ति के बिना भी आय प्राप्त हो सकती है। यदि निर्धारिती को आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि आय उसे प्राप्त हुई है, हालांकि इसे बाद में सुनिश्चित होने पर प्राप्त किया जा सकता है। मूल अवधारणा यह है कि उसने आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया होगा।(देखें ई.डी. ससून एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सी.एल.टी. बॉम्बे सिटी)।

जैसा कि सी.एल.टी. में न्यायिक समिति द्वारा बताया गया है, बॉम्बे प्रेसीडेंसी और अदन बनाम चुन्नीलाल बी. मेहता, उस स्थान को निर्धारित करने के लिए कोई सामान्य परीक्षण करना असंभव है जहां व्यवसाय का लाभ अर्जित होता है। कुछ मामलों में यह अनुबंध के गठन का स्थान हो सकता है, लेकिन अन्य मामले - उदाहरण के लिए वह स्थान जहां अनुबंध किया जाता है या अनुबंध के तहत कार्य किए जाते हैं - कुछ परिस्थितियों में निर्णायक हो सकते हैं। जब व्यवसाय में सामान खरीदना और बेचना शामिल होता है, तो लाभ अर्जित होता है उस स्थान पर एक सामान्य नियम जहां बिक्री का अनुबंध किया जाता है या जहां बिक्री की जाती है। लेकिन प्रश्न बहुत हद तक प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रिपोर्ट के पृष्ठ 533 पर न्यायिक समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

“उनके आधिपत्य सभी वर्गों के विदेशी लेनदेन, या यहां तक कि माल की बिक्री के संबंध में सामान्य आवेदन का कोई नियम नहीं बना रहे हैं। ऐसा करना लगभग असंभव और पूरी तरह से नासमझी होगी - एरिचसेन बनाम लास्ट में लॉर्ड एशर की भाषा का उपयोग करना स्वाभाविक है। वे यह नहीं कह रहे हैं कि अनुबंध के गठन का स्थान बाकी सभी चीजों के विपरीत है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन अन्य मामले - उदाहरण के लिए, अनुबंध के तहत किए गए कार्य - को प्राथमिकता से इंकार नहीं किया जा सकता है। बोर्ड के समक्ष मामले में अनुबंध ब्रिटिश भारत में न तो तैयार किए गए थे और न ही लागू किए गए थे; उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि ब्रिटिश भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न हुआ मुनाफा अच्छी तरह से आधारित है।"

इस मामले में पाए गए तथ्यों के संदर्भ में हमारी राय है कि अपीलकर्ता को उस स्थान पर लाभ हुआ जहां बिक्री हुई थी; दूसरे शब्दों में, जहां माल में संपत्ति खरीददारों के पास चली गई। वर्तमान मामले में समस्या यह निर्धारित करना है कि क्या माल में संपत्ति भीलवाड़ा में खरीदारों को दी गई, जैसा कि अपीलकर्ता ने दावा किया है, या कोडरमा या गिरिडीह में, जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया है। अज्ञात वस्तुओं की बिक्री के अनुबंध के मामले में संपत्ति क्रेता के पास नहीं जाती है जब तक कि अनुबंध के तहत वितरण योग्य स्थिति में माल का बिना शर्त विनियोग न हो।

भारतीय माल बिक्री अधिनियम की धारा 23 (1930 का अधिनियम 3) कहती है-

“1) जहां बिक्री का अनुबंध है निश्चित या भविष्य के माल उस विवरण का सामान और एक वितरण योग्य में राज्य को बिना शर्त विनियोजित किया जाता है अनुबंध या तो विक्रेता द्वारा उसकी सहमति से क्रेता द्वारा या क्रेता द्वारा विक्रेता की सहमति से, माल में संपत्ति क्रेता के पास चली जाती है। ऐसी सहमति व्यक्त या निहित हो सकती है और विनियोजन से पहले या बाद में दी जा सकती है।

(2) जहां, अनुबंध के अनुसरण में, विक्रेता खरीदार को ट्रांसमिशन के उद्देश्य से माल को खरीदार या वाहक या अन्य जमानतदार (चाहे खरीदार द्वारा नामित किया गया हो या नहीं) को वितरित करता है, और अधिकार सुरक्षित नहीं रखता है निपटान के मामले में, यह माना जाता है कि उसने माल को अनुबंध में बिना शर्त विनियोजित कर दिया है।

धारा 25 इस प्रकार प्रदान करती है-

" (1) जहां विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई अनुबंध है या जहां सामान बाद में अनुबंध के लिए विनियोजित किया जाता है, विक्रेता, अनुबंध या विनियोग की शर्तों के अनुसार, कुछ शर्तों के पूरा होने तक माल के निपटान का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। पूरा हुआ ऐसे मामले में, खरीदार को माल की डिलीवरी के बावजूद, या खरीदार को ट्रांसमिशन के उद्देश्य से वाहक या अन्य जमानतदार को, माल में

संपत्ति खरीदार को नहीं मिलती है जब तक कि विक्रेता द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी की जाती हैं।

(2) जहां माल भेजा जाता है और लदान के बिल द्वारा माल विक्रेता या उसके एजेंट के आदेश पर वितरित किया जाता है, विक्रेता को प्रथम दृष्टया निपटान का अधिकार सुरक्षित माना जाता है। ....."

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने प्रेषण के समय माल पर निपटान का अधिकार सुरक्षित रखा है। खेप "सेल्फ" भेजी गई थी, रेलवे रसीद अपीलकर्ता के नाम पर ली गई थी और विनिमय बिल के साथ रेलवे रसीद अपीलकर्ता द्वारा राजस्थान बैंक को प्रस्तुत की गई थी। राजस्थान बैंक के पक्ष में रेलवे रसीद का समर्थन करने के बाद वसूली खरीदारों को सामान तभी वितरित किया जाता था जब वे बैंक को भुगतान करते थे और अपने पक्ष में रेलवे रसीद प्राप्त करते थे। तथ्य यह है कि माल हैं लदान के बिल द्वारा, विक्रेता के आदेश पर सुपुर्दगी योग्य बनाया गया; या उसके एजेंट के पास निपटान के अधिकार का प्रथम दृष्टया आरक्षण है ताकि संपत्ति को क्रेता के पास जाने से रोका जा सके।अगर टाइल विक्रेता अनुबंध मूल्य को सुरक्षित करने के लिए, लदान के बिल के साथ सौदा करता है, या उसे बनाए रखने का दावा करता है, जैसे कि जब वह विनिमय के बिल के साथ लदान के बिल को इस निर्देश के साथ भेजता है कि विनिमय बिल की स्वीकृति या भुगतान होने तक क्रेता को लदान का वितरण नहीं किया जाना चाहिए, विनियोग पूर्ण नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट की स्वीकृति तक या भुगतान मूल्य की निविदा, केवल सशर्त है, और ऐसी स्वीकृति या भुगतान या निविदा तक, माल में संपत्ति क्रेता के पास नहीं जाती है।- (मिराबिता बनाम इंपीरियल ओटोमन बैंक)। यदि विक्रेता खरीदार को बैंक से ड्राफ्ट पर छूट देता है, और बैंक को खरीदार को विक्रेता के आदेश के अनुरूप लेन-देन का बिल सौंपने और ड्राफ्ट की स्वीकृति पर उसके द्वारा रिक्त स्थान पर पृष्ठांकित करने के लिए अधिकृत करता है, सामान्य व्यापारिक समझ के अनुसार, अनुमान लगाने का इरादा यह है कि विक्रेता का इरादा; ड्राफ्ट स्वीकार होने पर स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए, लेकिन ऐसा होने तक मालिक बने रहने का भी इरादा रखता है। इसलिए, जब विक्रेता क्रेता पर हुंडी या विनिमय का बिल खींचता है और क्रेता के सम्मान पर रेलवे रसीद की डिलीवरी के उद्देश्य से अपने स्वयं के बैंकर को हुंडी या विनिमय के बिल को संबंधित रेलवे रसीद के साथ सौंपता है, माल में संपत्ति को क्रेता के पास तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक वह कीमत का भुगतान नहीं कर देता और

बैंकर से रेलवे रसीद की डिलीवरी नहीं ले लेता। प्रिंज़ एडलबर्ट में लॉर्ड स्मनर द्वारा इस मामले को बहुत स्पष्ट रूप से इस प्रकार रखा गया है:

"जब एक मालवाहक अपना ड्राफ्ट लेता है जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन वह इस तरह से पृष्ठांकित किए गए लदान बिल के साथ लेता है, और इसे एक बैंकर के साथ छूट देता है, तो वह खुद को 'दराज के रूप में उपकरण' पर उत्तरदायी बनाता है, और वह आगे माल बनाता है, जो जेडिंग का बिल उसके भुगतान के लिए सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।

यदि, बदले में, डिस्काउंटिंग बैंकर अपनी स्वीकृति के विरुद्ध लदान बिल को स्वीकर्ता को सौंप देता है, तो निष्कर्ष यह है कि वह बिल पर पार्टी की इस अतिरिक्त देनदारी को प्राप्त करने के विचार में अपनी गोपनीयता से अलग होने से संतुष्ट है, और वह ऐसा करने में वह 'प्रेषक और दराज' के आदेश के अनुसार कार्य करता है। लदान के पृष्ठांकित बिल का कब्ज़ा स्वीकर्ता को जहाज के आगमन पर माल का कब्ज़ा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, यदि भेजने वाला माल का मालिक है। बैंकर को, जिसके प्रति वह स्वयं उत्तरदायी है और जिसका हित ड्राफ्ट स्वीकार होने तक लदान बिल को जारी रखने में है, ड्राफ्ट की स्वीकृति के विरुद्ध लदान बिल को सरेंडर करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करता है, ऐसा होने पर यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि वह मालिक-शिप को स्थानांतरित करने का इरादा रखता है। लेकिन जब तक यह पूरा नहीं हो जाता तब तक मालिक बने रहने का भी इरादा है .....आम तौर पर इन परिस्थितियों में क़ानून का अनुमान है कि माल में स्वामित्व 'तब हस्तांतरित किया जाता है जब उनके विरुद्ध तैयार किया गया मसौदा स्वीकार कर लिया जाता है।'

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि रेलवे रसीदें बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित होने के बाद और अपीलकर्ता को रेलवे रसीदों की छूट द्वारा प्रतिफल प्राप्त होने के बाद माल का स्वामित्व अपीलकर्ता से बैंक ऑफ राजस्थान को चला गया था। जो उसके बाद खरीददार का एजेंट बन गया। हमें नहीं लगता कि इस तर्क में कोई दम है। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का मामला यह था कि रेलवे रसीद और बिल भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों के खरीदारों से संग्रह के लिए बैंक को भेजे गए थे। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह माना गया कि 8 जुलाई, 1948 को अपीलकर्ता द्वारा लिखा गया कथित पत्र एक नकली दस्तावेज था और अपीलकर्ता

के बिलों में छूट के लिए राजस्थान बैंक को कोई निर्देश नहीं दिया गया था। यह मानते हुए भी कि बैंक ने कुछ बिलों की राशि का कुछ हिस्सा अपीलकर्ता को क्रेडिट कर दिया, बैंक के डिस्काउंट फॉर्म में निर्दिष्ट शर्तों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की जिम्मेदारी तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक कि बैंक को भुगतान प्राप्त नहीं हो गया। बैंक का डिस्काउंट फॉर्म प्रदान किया गया:

“बैंक माल भेजने वाले के जोखिम पर माल भेज रहा है। . . . . . यदि क्रेता द्वारा बिल का अनादर किया जाता है तो जिम्मेदारी भेजने वाले की होगी और बैंक को उससे राशि वसूल करने का अधिकार होगा। यदि क्रेता से राशि वसूल नहीं की जाती है, तो बैंक को प्रेषक के खाते में राशि डेबिट करने का अधिकार है।"

यह स्पष्ट किया गया कि जब अपीलकर्ता ने बैंकर के साथ हुंडी पर बातचीत की, तो उसने ऐसा केवल अपने बैंकिंग व्यवसाय के एक हिस्से के रूप में किया। भले ही बैंकर द्वारा हुंडी की खरीदारी की गई हो, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि माल की बिक्री हुई थी । पहला, बैंकर का माल की बिक्री के लिए बैंकर और विक्रेता के बीच कोई समझौता नहीं था। दूसरे, बैंकर के पास माल पर केवल तब तक सुरक्षा होती थी जब तक खरीदार द्वारा कीमत का भुगतान नहीं किया जाता। अन्यथा रखने का मतलब यह होगा कि विक्रेता ने खरीदार के साथ अनुबंध का उल्लंघन किया और बैंकर को माल बेच दिया। हालाँकि, ऐसा नहीं है। अपीलकर्ता ने केवल सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अनुसार खरीदार के साथ अनुबंध किया। इसलिए यदि बैंक द्वारा अपीलकर्ता को हुंडी की कीमत के रूप में कोई पैसा दिया गया था तो वह किसी भी अर्थ में माल की बिक्री का पैसा नहीं था और बैंक उसके क्रेता के रूप में कार्य नहीं कर रहा था दूसरी ओर, बैंक द्वारा सैकड़ों लोगों का पीछा करना एक सुविधाजनक व्यवस्था थी- बैंक और उसके अपने ग्राहक के बीच और अपीलकर्ता द्वारा क्रेडिट को फ्रीज करने से बचने के लिए यह उसके सामान्य बैंकिंग लेनदेन के दौरान किया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बेची गई वस्तुओं की कीमत केवल तभी अर्जित मानी जा सकती है जब खरीदार कीमत का भुगतान करता है या बैंक के साथ एक समझौता करता है जो हुंडी का समर्थन करता है; तब तक, बाद वाले को अपीलकर्ता के खिलाफ सहारा लेने का अधिकार होगा यदि हुंडी का अनादरित होती है। वर्तमान मामले में, भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में कोडरमा और गिरिडीह में खरीदारों को स्वामित्व पारित होने पर ही अपीलकर्ता खरीद धन का

हकदार बन गया और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता को भाग 'ए' और भाग 'सी' राज्यों में अर्जित आय थी।

हम अपीलकर्ता के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात्, अभ्रक को भाग 'बी' राज्य में भीलवाड़ा में निकाला गया, संसाधित किया गया, छांटा गया, पैक किया गया और भेजा गया और आय का एक हिस्सा भीलवाड़ा में जमा हुआ और अपीलकर्ता, किसी भी मामले में, प्रभाजन का दावा करने का हकदार था। अर्जित लाभ अपीलकर्ता की ओर से वकील ने सी.एल.टी., बॉम्बे बनाम अहमदभाई उमरभाई एंड कंपनी और द एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम सी.आई.टी. में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया। मद्रास, जहां यह बताया गया कि समग्र व्यवसाय के मामले में, उदाहरण के लिए जहां एक व्यक्ति विनिर्माण करता है- विनिर्माण और बिक्री व्यवसाय में यह कहना संभव नहीं था कि एकमात्र स्थान जहां से उसे लाभ होता है वह बिक्री का स्थान है। लाभ उसे सबसे पहले एक निर्माता के रूप में उसके व्यवसाय के लिए प्राप्त होता है और दूसरा उसके व्यापारिक संचालन के लिए प्राप्त होता है और लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार लाभ और हानि को इन व्यवसायों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में इस तर्क को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लाभ के बंटवारे का सवाल नहीं उठाया, न ही इस पर विचार किया गया और न ही निर्णय लिया गया। सी.आई. टी. में बॉम्बे बनाम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड इस न्यायालय द्वारा बताया गया था कि जब कानून का कोई प्रश्न न तो ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाया जाता है और न ही उस पर विचार किया जाता है तो यह ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न होने वाला प्रश्न नहीं होगा और उच्च न्यायालय ऐसे किसी भी प्रश्न से निपटने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करेगा। हम तदनुसार मानते हैं कि श्री कारखानिस मामले के इस पहलू पर अपना तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

इन कारणों से हमारा मानना है कि इन अपीलों को डिसमिस कियाजाना चाहिए कोस्ट्स पर- वन हियरिंग फी।

अपील खारिज की जाती है।

अनुवादित द्वारा-

रीमा बंसल

अपर जिला जज (त्वरित न्यायालय)

हापुड़।